

प्रेषक,

उमेश कुमार,  
प्रमुख सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा0 उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट

लखनऊ दिनांक 22 मार्च,2018

विषय- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा उपकरणों की स्थापना के लिए अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-11/2016/142/सात-न्याय-9(बजट)-2016-800(51)/2012 दिनांक 20-01-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा उपकरणों की स्थापना के लिए ₹0 2851.61 लाख के आगणन पर प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रथम किश्त के रूप में ₹0 200.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है । पुनः शासनादेश सं0-135/2017/1797/सात-न्याय -9(बजट)-2017-800(51)/2012\_दिनांक 20-11-2017 के माध्यम से ₹0300.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है ।

2- तत्क्रम में निबन्धक (प्रोटोकाल) मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र सं0-4378/निबन्धक (प्रोटोकाल) दिनांक 15-03-2018 के क्रम में अनुमोदित लागत ₹02851.61 लाख के सापेक्ष ₹0200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किय जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1 चूंकि उक्त निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, कार्यदायी संस्था नामित है । अतः उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, के सम्बन्धित अधिकारी , को उपलब्ध कराने हेतु महानिबन्धक उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अधिकृत किया जाता है।

2 स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

3 शासनादेश सं0-11/2016/142/सात-न्याय -9(बजट)-2016-800(51)/2012\_दिनांक 20-01-2016 की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे ।

4 लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

5 स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, तथा समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

6 प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस - 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी ,2010 में दिये गये निर्देशों का कडायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- 01-कार्यालय भवन- 051-निर्माण - 04-मा0 उच्च न्यायालय में निर्माण-00- 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र (मतदेय), के नामे डाला जायेगा

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त,2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारो के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)

प्रमुख सचिव

सं0- 39 /2018/276(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) 30प्र0, इलाहाबाद ।
- 3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ ।
- 4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, इन्दिरा भवन सिविल लाइन इलाहाबाद ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
- 7- अपर परियोजना प्रबन्धक (वि0) 30प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विद्युत इकाई-वाराणसी
- 8- वित्त ई- 12/ आय-व्ययक अनुभाग- 1 ।
- 9- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

( सन्त लाल )

उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।